

EXCAVATION OF CAPITAL OF 'HARSHA VARDHANA'

*84. SHRI SWAISINGH SISODIA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government are seeking assistance from the UNESCO to excavate the remains of the capital of the Seventh Century Hindu King Harsha Vardhana, believed to be buried somewhere in Haryana ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) At present there is no such proposal under consideration of the Government of India.

(b) Does not arise.

REFERRING OF THE QUESTIONS OF PRIVY PURSE TO THE SUPREME COURT

*85. SHRI NIRANJAN VARMA :

SHRI C. D. PANDE :

SHRI M. V. BHADRAM :

SHRI BALACHANDRA MENON :

SHRI S. G. SARDESAI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether prominent political leaders including Shri A. B. Vajpayee, Shri M. R. Masani and Shri Banka Behary Das and some Members of Parliament have written to the President urging that the questions of privy purses be referred to the Supreme Court under Article, 143 of the Constitution and its authentic opinion sought ;

(b) if so the names of the Members of Parliament other than those referred to above who have written to the President in this regard ; and

(c) the Government's reaction to this suggestion ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b) The Ruler of Baroda and Sarvashri A. B. Vajpayee, M. R. Masani, Prakash Vir Shastri and Sriraj Meghraj of Dhrangadhra, Members of Parliament had written to the President on the subject.

(c) While Government consider that it is not necessary to seek the opinion of the Supreme Court the representations made to the President are under examination.

दिल्ली प्रशासन में वाइस प्रिंसिपलों के पद

*86. श्री गणेशी लाल चौधरी : क्या शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के गृह कार्य मंत्रालय के आदेश दिनांक 11 जुलाई, 1968 के अनुसार जिन ग्रेडों अथवा नौकरियों में कुल रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक स्थानों की सीधी भर्ती नहीं होती है उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिन जातियों के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्थान पदोन्नति के कोटे में सुरक्षित रखे गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में वाइस प्रिंसिपलों के पदों पर पदोन्नति के मामले में इन आदेशों की अवहेलना की गई है ;

(ग) पिछले तीस वर्षों में वाइस प्रिंसिपलों के पदों पर कितनी पदोन्नतियां की गईं और उन में से कितनी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अध्यापकों को मिली ;

(घ) क्या ये पदोन्नतियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए नियत किये गये प्रतिशत के अनुसार हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो इन पदों पर उनके लिए पूरा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?